



2026:AHC:49182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या -8878 वर्ष 2026

अब्दुल रब

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार मिश्र, मो. जैद

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पांडे,सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जैद, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 5/गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. पांडे को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी संख्या 4-तहसीलदार (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा द्वारा वाद संख्या आरएसटी /9650/2021 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202113380109650) में दिनांक 28.08.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है; तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 3-अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील एवं जिला अमरोहा द्वारा वाद संख्या 1570/2025,कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी202513380001570 में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता, यू पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-ए के संरक्षण का हकदार है। संबंधित अधिकारियों ने



उपर्युक्त आदेश पारित करते समय मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 4-तहसीलदार (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा

WRIC संख्या 8878 वर्ष 2026

2

द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसे यू पी. राजस्व संहिता, 2016 के नियम 67 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

4. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एक तर्क यह भी उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश, 'ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2023 (1) ए डी जे 154) मामले में पारित निर्णय के पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे; अतः इन आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।

5. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

6. इसी के मद्देनज़र, चूंकि दिनांक 28.08.2025 और 29.01.2026 के आदेश ऋषिपाल (सुप्रा) के मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, अतः वे रद्द किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **स्वीकार** की जाती है। खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं।

8. प्रतिवादी संख्या 4 - तहसीलदार (न्यायिक), मंडल मुरादाबाद, तहसील अमरोहा, जिला अमरोहा को निर्देश दिया जाता है कि वे कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः आज से चार माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करें।

9. इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई हेतु इस आदेश की सूचना प्रत्यर्थी संख्या 2—जिला मजिस्ट्रेट, जिला अमरोहा को प्रेषित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,)



10 मार्च, 2026

टी.एस.